the team was also apprised of growing financial and developmental needs of the State in view of the gradual improvement in the law and order situation and the reactivation of the development administration that has become possible due to the sustained and concerted efforts on the parts of the Central and State Government. The Centre is providing Special Central Plan Assistance to meet the resource gap on Non-plan side so that the Plan Outlays fixed for the State can be spent entirely on development works/programmes without diversion to bridge Non-plan gaps as in the last few years.

Government's stand on talk with militants

527. SHRI JAGMOHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have recently changed its earlier stand of talking to Kashmir militants only within the framework of the Indian Constitution to now talking to them even outside the Constitution;

4 (b) if so, what are the reasons thereof; and

(c) what has been the reaction of the militants, orgaisations to the change?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

बड़े उद्योगों द्वारा "सेनीटरी टॉवल" का उत्पादन

528. **श्री राम जेठमलानी** :

श्रीमती सुष्मा स्वराज :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "सेनीटरी टॉवल" का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र की आरक्षित सूची में हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि कतिपय बड़ी और बहुराष्ट्रिय कंपनियों को "सेनीटरी टॉवल" का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं,

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है तथा यह देश की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत होगी,

(घ) क्या यह भी सच है कि इन संगठनों की निर्यात वचनबद्धता 75 प्रतिशत है,

(ड़) यदि हां, तो क्या इन संगठनों ने इन वर्षो के दौरान इस करार का उल्लघंन किया है, और

(च) यदि हां , तो इन उल्लंघनों का लघु उद्योगों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना निम्नलिखित हैं :-

- आरक्षण से पूर्व बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्ज जानसन एण्ड जानसन इंडिया लिमिटेड को प्रतिवर्ष सेनीटरी प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स और सेनीटरी पेड़ों के 6 मिलियन नग के विनिर्माण के लिये अनुमति दी गई थी।

- दूसरी बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्ज प्रोक्टर एण्ड गैम्बल इंडिया लिमिटेड को 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व की शर्त पर प्रतिवर्ष दस करोड़ पोलीथीलीन नेटिंग सेनीटरी पैडों के विनिर्माण की क्षमता आशय पत्र 1992 में दिया गया था।

- मैसर्ज एम.आर.एस. हाईजीन प्रोडक्टस लिमिटेड दिल्ली को 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व की शर्तो पर प्रतिवर्ष सेनीटरी नेपकिन के 144 मिलियन नग की उत्पादन क्षमता का आशय पत्र 1991 में दिया गया था।

(ड़) और (च) कुछेक बड़े उद्योग एककों द्वारा करार के उल्लंघन संबंधी शिकायतें प्राप्त की गई हैं और इन शिकायतों की जांच की जा रही है । यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो इन कम्पनियों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की जायेगी।

Utilisation of Funds for Wasteland Development

529. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether vast sums of money have been wasted into wasteland development over the last three years;

(b) the details of the amount invested in the development of wastelands; and

(c) the results on this investment in the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF WASTLANDS DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c) Tree planting/afforestation activities are carried out under Point No. 16 of the 20-Point Programme on land including wastelands. An amount of